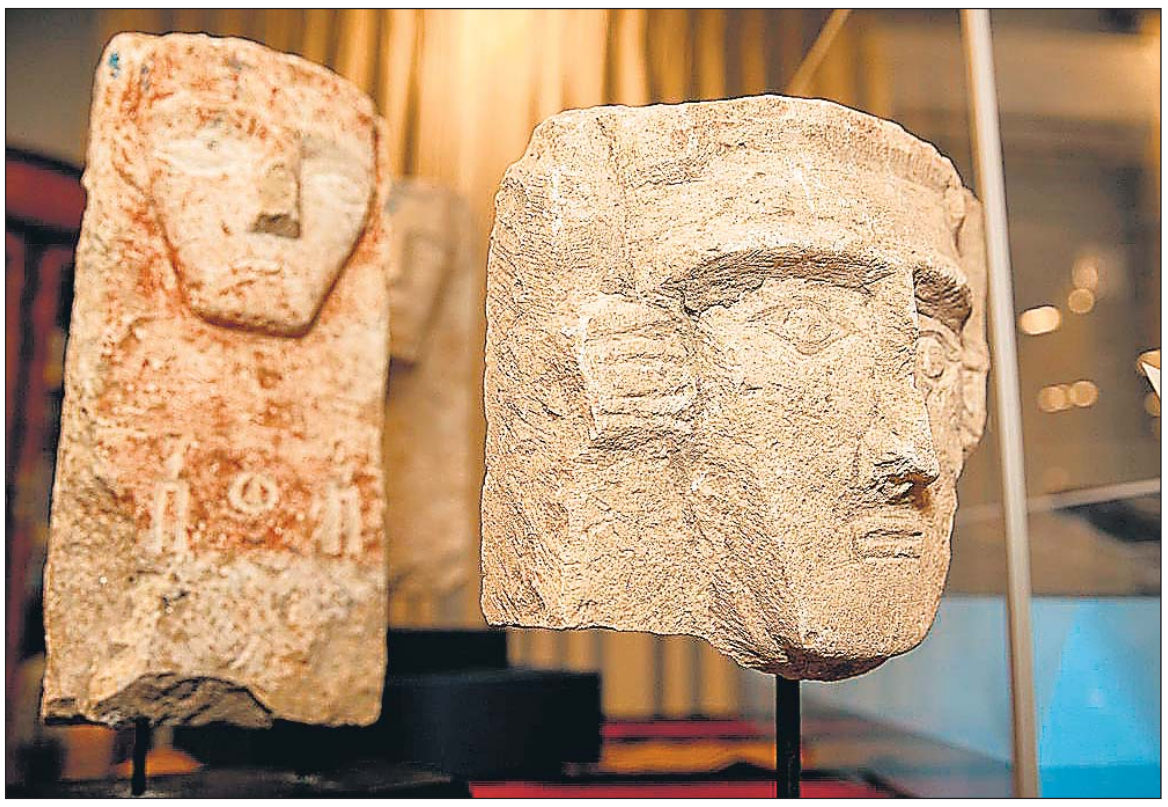

यमन से चुराई गई 77 कलाकृतियाँ अमेरिका उसे लौटा रहा है, लेकिन फिलहाल ये कलाकृतियाँ स्मिथसोनियन नैशनल म्यूज़ियम ऑफ एशियन आर्ट में रखी जाएंगी। यू.एस.ए. में यमन के राजदूत मोहम्मद अल हधरामी ने कहा, "यमन में व्याप्त अशांति और हिंसा को देखते हुए कलाकृतियों को यमन वापस लाना ठीक नहीं है और स्मिथसोनियन दो साल के लिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए मान गया है।" उन्होंने कहा, स्मिथसोनियन का नैशनल म्यूज़ियम ऑफ एशियन आर्ट कल्चर, हैरिटेज और संरक्षण के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर है और हमें खुशी है कि, यह सामान उनकी देखरेख में है। इन 77 कलाकृतियों में, जो बीस सालों में पहली बार अमेरिका यमन को लौटा रहा है, कांसे की एक कटोरी, प्राचीन कुरान के 11 मुड़े हुए पन्ने तथा ईसा पूर्व पहली सदी के 65 नक्काशीदार पत्थर शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने एक दशक पहले एक न्यूयॉर्क आर्ट डीलर से ये कलाकृतियां जब्त की थीं। कई वर्षों से ये स्टोरेज में थीं और अब जल्दी ही, नई पार्टनरशिप के तहत ये कलाकृतियाँ सार्वजनिक हो सकती हैं। म्यूज़ियम के डायरैक्टर, चेज़ एफ. रॉबिन्सन ने बताया कि, "हमारे संरक्षक और क्यूरेटर इस क्षेत्र में लम्बे समय से सक्रिय थे। हम बहुत जल्दी समझ गए थे कि, हमें यह करना ही होगा।" म्यूज़ियम ने इन कलाकृतियों के प्रदर्शन की अनुमति दे दी है और यमन के लोगों से सम्पर्क कर इनका ब्यौरा भी लिया जा रहा है। म्यूज़ियम इन कलाकृतियों की कहानी सामने लाना चाहता है तथा विश्व का ध्यान यमन की अशांति की ओर आकर्षित करना चाहता है।

राइट-टू-हैल्थ बिल के विरोध में आज जयपुर में महारैली निकालेंगे डॉक्टर्स

आंदोलनकारी निजी चिकित्सकों और सरकार के बीच सोमवार को हुई वार्ता फिर बेनतीजा रही

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। 'राइट-टू-हैल्थ' बिल पर निजी चिकित्सकों और राज्य सरकार के बीच सोमवार को एक बार फिर वार्ता बेनतीजा रही। ऐसे में प्रदेश में लगातार 16वें दिन भी निजी अस्पतालों में मरीजों का उपचार नहीं हो सका। चिरंजीवी और आर.जी.एच.एस. योजनाओं में मुफ्त इलाज तो दूर लोगों को पैसे चुकाने के बाद भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। उधर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल समेत प्रदेश के तमाम छोटे-बड़े अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस गतिरोध के बीच आंदोलनरत निजी डॉक्टर्स मंगलवार सुबह 11 बजे जयपुर में महारैली निकालकर 'राइट-टू-हैल्थ' बिल का विरोध जताएंगे। दावा किया जा रहा है कि राजस्थान और अन्य राज्यों से भी डॉक्टर्स इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। यह भीड़ करीब 4 लाख होने की संभावना है।

- डॉ. विजय कपूर का दावा है कि, जयपुर के 218 अस्पतालों ने सरकारी स्कीम बंद करने की लिखित सहमति दे दी है, अन्य 21 जिलों के प्राइवेट अस्पताल भी इस बारे में अपनी सहमति दे चुके हैं।
- बीते 16 दिनों से प्रदेश के निजी अस्पतालों में उपचार को तरस रहे हैं मरीज।
- जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल समेत प्रदेश के तमाम सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है।

जानकारी के मुताबिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स सोसाइटी के सचिव डॉ.विजय कपूर के नेतृत्व में 6 चिकित्सकों का प्रतिनिधिमंडल सोमवार दोपहर सचिवालय पहुंचा। जहां उनकी चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी.रविकांत से वार्ता हुई। वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरी हुई लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। डॉक्टरों ने कहा कि सरकार 'राइट-टू-हैल्थ' बिल के प्रावधानों को पहले सरकारी अस्पतालों पर ही लागू करे, इसका नतीजा देंखे, उसके बाद निजी अस्पतालों को इसके दायरे में लाया जाये। उधर टी. रविकांत का कहना था कि डॉक्टर्स के सुझावों को रूल्स में ले लिया जायेगा। उनकी इस बात पर डॉक्टर्स राजी नहीं हुए। ऐसे में चिकित्सकों ने अपने आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ होने वाली वार्ताओं के दौर के बीच भी आंदोलन तब तक जारी रखा जाएगा, जब तक कि कोई समाधान नहीं होता।

डॉ. विजय कपूर का दावा है कि 'राइट-टू-हैल्थ' बिल के विरोध में जयपुर के 218 निजी अस्पतालों ने सरकारी योजना को बंद करने के लिए लिखित में अपनी सहमति दे दी है। वहीं प्रदेश के 21 जिलों से शत प्रतिशत चिकित्सालयों ने सरकारी स्कीम्स के मास डीएम्पेनलमेंट के लिखित आवेदन दे दिए है।

मंगलवार को 'राइट-टू-हैल्थ' बिल के विरोध में एक बार फिर चिकित्सक महारैली का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें पिछले दिनों आयोजित की गई रैली से भी अधिक संख्या में चिकित्सक भाग लेंगे। इस बार चिकित्सकों को अन्य राज्यों से भी समर्थन मिल रहा है।

'छह साल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नियुक्ति तिथि से गणना कर चयनित वेतनमान दिया जाए। इसके बावजूद भी अब तक आदेश की पालना नहीं की गई। वहीं विभाग की ओर से आदेश की पालना के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया। इस पर अदालत ने विभाग को 5 अप्रैल तक का समय देते हुए कहा है कि पालना नहीं होने पर विभाग के सचिव हाजिर होकर अपना स्पष्टीकरण पेश करें।

'इंग्लिश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने महात्मा गांधी स्कूलों में अध्यापन के लिए गत 15 जनवरी को नौ हजार से अधिक पदों के लिए सहायक अध्यापक संविदा भर्ती निकाली। इसमें सिर्फ उन अभ्यर्थियों को ही पात्र माना गया है, जो अंग्रेजी माध्यम से हैं। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता हिंदी विषय से स्नातक है, लेकिन उसके पास वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी थी। वहीं उसने बीएड और रीट भी अंग्रेजी विषय से ही पास की है। इसके बावजूद उसे पात्र नहीं माना जा रहा है। याचिका में कहा गया कि एनसीटीई के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अंग्रेजी माध्यम वाला अभ्यर्थी ही इन स्कूलों में पढ़ा सकता है। नियमों में सिर्फ अध्यापक पात्रता परीक्षा और बीएड पास होने की ही शर्त है। याचिका में यह भी कहा गया कि विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार ने महात्मा गांधी स्कूलों की स्थापना की है। शुरुआत में अन्य सरकारी स्कूलों के हिंदी माध्यम वाले शिक्षकों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन कर इन स्कूलों में लगाया गया था। ये हिंदी माध्यम के शिक्षक वर्तमान में भी इन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। हिंदी माध्यम से पास अभ्यर्थी को भर्ती में शामिल नहीं करने का विभाग का आदेश मनमाना है। ऐसे में याचिकाकर्ता को भी भर्ती के लिए पात्र माना जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

दिवंगत गायक मूसेवाला की तरह नवजोत सिद्धू की सुरक्षा भी घटाई

सिद्धू ने पलटवार करते हुए पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा, जैसे दिवंगत मूसेवाला के साथ हुआ ठीक वैसा अब मेरे साथ भी हो रहा है

- नवजोत सिद्धू की सुरक्षा "ज़ैड प्लस" से कम कर "वाई प्लस" कर दी गई है।
- सिद्धू सोमवार को दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के घर उनके परिजनों से मिलने पहुंचे।

चंडीगढ़, 3 अप्रेल। जेल से रिहा पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा घटा दी गई है। उनकी सुरक्षा जेड प्लस से कम कर वाई प्लस कर दी गई है। सोमवार को दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के घर उनके परिजनों से मिलने पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू ने सुरक्षा घटाने पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि जो मूसेवाला के साथ हुआ, वही मेरे साथ हो रहा है। वह चाहते हैं कि मैं घर से न निकलूं लेकिन मुझे किसी का भय नहीं है। पंजाब में कानून व्यवस्था डगमगा गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। पुलिस कमजोर नहीं होती, उसको ऑर्डर कमजोर करते हैं।

इससे पहले नवजोत सिद्धू ने सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह, माता चरण कौर और ताया चमकौर सिंह के साथ दुख साझा किया। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि वह परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। बलकौर सिंह ने जेल से लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू पर कहा कि बेशक इस पर कमेटी बना दी है लेकिन यह नहीं बताया कि इसकी रिपोर्ट कब आएगी। वहीं, सिद्धू ने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है कि पंजाब का नाम चमकाने वाले की सुरक्षा हटा ली गई और गैंगस्टरों को जेड सिक्योरिटी दी जा रही है।

नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि सरकार ने अगर सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा वापस ली थी तो उसकी जानकारी को सार्वजनिक क्यों किया? मूसेवाला की हत्या के पीछे कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है। मुझे चुप करवाने के लिए भी सरकार ने मेरी सुरक्षा वापस ले ली है। जो कुछ सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ, वह मेरे साथ हो रहा है लेकिन मैं सच बोलने से रुकने वाला नहीं। पंजाब में गैंगस्टरों के प्रभाव पर सिद्धू ने कहा कि पंजाब की जेलें सुधार घर के बजाय अपराध का सुविधा सेंटर बन गई हैं। नौजवान पंजाब में रहने को तैयार नहीं हैं। वे विदेश जा रहे है। गलत संगत में पड़े नौजवानों का इस्तेमाल कर उनसे वारदातें करवाई जा रही हैं।

भारत को उकसाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है चीन

नई दिल्ली, 3 अप्रेल। भारत ने हाल ही में सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश में जी20 कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत एक अहम बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में चीन शामिल नहीं हुआ था। अब कुछ दिन बाद उसने एक बार फिर भारत को उकसाने की कोशिश की है। उसने अरुणाचल प्रदेश के लिए मानकीकृत नामों की तीसरी लिस्ट जारी की है। इसमें अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम

- चीन ने अपनी स्थानीय भाषा में अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम जारी किये।

बताए गए हैं। उसने ये नाम चीनी, तिब्बती और पिनयिन वर्णों में जारी किए हैं।

चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश के लिए 11 स्थानों के मानकीकृत नाम जारी किए। वह अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी चीन का हिस्सा बताता है और इसे जांगनान कहता है।

'हमें भ्रष्टाचार विरासत में प्राप्त हुआ है'

मोदी ने सी.बी.आई. की स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण होने की मौके पर आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही

- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सी.बी.आई. को अपने काम में जरा भी हिचकने या ढील देने की जरूरत नहीं है।
- मोदी ने कहा कि, न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सी.बी.आई. हर जुबान पर है। अपनी कार्यप्रणाली, कार्यकुशलता और क्षमताओं से सी.बी.आई. ने लोगों में अपने प्रति गहरी आस्था का भाव जगाया है।

नई दिल्ली, 3 अप्रैल (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भ्रष्टाचार को लोकतंत्र एवं न्याय का शत्रु तथा गरीबी एवं अपराध का मूल बताते हुए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) को आज साफ निर्देश दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में पूर्ण राजनीतिक इच्छाशक्ति है और सी.बी.आई. को अपने काम में जरा भी हिचकने या ढील देने की जरूरत नहीं है।

मोदी ने आज यहां विज्ञान भवन में सी.बी.आई. के हीरक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। समारोह में प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्मिक, प्रशिक्षण एवं जनशिकायत राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एवं कैबिनेट सचिव राजीव गौबा भी उपस्थित थे। इस मौके पर सी.बी.आई. के मामलों से जुड़े उच्चतम न्यायालय का संग्रह भी जारी किया गया।

मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश की प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में 60 वर्ष का सफर सी.बी.आई. ने पूरा किया है। ये छह दशक निश्चित रूप से अनेक उपलब्धियों के रहे हैं। सी.बी.आई. ने अपने काम से, अपने कौशल से सामान्यजन को एक विश्वास दिया है।

उन्होंने कहा, आज भी जब किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है तो आवाज उठती है कि मामला सी.बी.आई. को दे देना चाहिए। लोग आंदोलन करते हैं कि केस उनसे लेकर सी.बी.आई. को दे दो। यहां तक कि पंचातय स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं कि इसे सी.बी.आई. को दे देना चाहिए।

मोदी ने कहा कि न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सी.बी.आई. हर जुबान पर है। अपनी कार्यप्रणाली, कार्यकुशलता और क्षमताओं से सी.बी.आई. ने लोगों में अपने प्रति गहरी आस्था का भाव जगाया है। सी.बी.आई. सत्य, न्याय के ब्रांड के रूप में उभरी है। आम लोगों से इस हद तक आस्था और विश्वास जीतना कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले छह दशक में सी.बी.आई. ने बहुआयामी और बहुक्षेत्रीय जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है, आज सी.बी.आई. का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। महानगर से लेकर जंगल तक सी.बी.आई. को दौड़ना पड़ रहा है।

राजेन्द्र राठौड़...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय वन एव पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव केन्द्रीय कानून मंत्री किरण रिजीजू, वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की। राजस्थान के सांसद व केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ी मीणा, घनश्याम तिवाड़ी, राजेन्द्र गहलोत आदि से भी राठौड़ ने शिष्टाचार भेट की तथा राज्य के हालात पर चर्चा की। इस दौरान नेताओं ने पुराने अनुभव भी साझा किए। गौरतलब है कि गुलाबचंद कटारिया के असम का राज्यपाल बनने के बाद से ही नेता प्रतिपक्ष का पद खाली पड़ा था। विधायकों ने सर्वसम्मति से राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष और सतीश पूनिया को उपनेता प्रतिपक्ष चुना है।

राहुल गांधी के शक्ति प्रदर्शन से भड़की भाजपा

भाजपा ने कांग्रेस की ओर से सूरत में आयोजित जमावड़े को कोर्ट पर दबाव बनाने का ड्रामा करार दिया

- केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव को अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया तो कांग्रेस चुप थी। पी. चिदंबरम और डी.के. शिवकुमार को भी समर्थन नहीं मिला, जो जमानत पर बाहर हैं। केवल राहुल गांधी के लिए कांग्रेस नाटक कर रही है, क्योंकि वे एक परिवार को भारत और उसके कानूनों से ऊपर मानते हैं।

सूरत, 3 अप्रेल। मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दो वर्ष की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को सूरत के सत्र न्यायालय पहुंचे तो उनके साथ कई दिग्गज नेता थे।

कांग्रेस इसे राहुल का समर्थन बता रही है, लेकिन भाजपा ने इसे कांग्रेस का ड्रामा करार दिया है। यही नहीं, आरोप लगाया है कि नेताओं की यह भीड़ न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए जुटाई गई।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी तीन कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर सूरत की जिला अदालत पहुँचे। यह सब कोर्ट पर दबाव बनाने का एक ड्रामा है।

न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने और राहुल की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद से भाजपा और कांग्रेस के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। सत्र न्यायालय में अपील के लिए राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे तो इस मुद्दे पर भी भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव को अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया तो कांग्रेस चुप थी। पी. चिदंबरम और डी.के. शिवकुमार को भी समर्थन नहीं मिला, जो जमानत पर बाहर हैं। केवल राहुल गांधी के लिए कांग्रेस नाटक कर रही है, क्योंकि वे एक परिवार को भारत और उसके कानूनों से ऊपर मानते हैं। अपील के लिए व्यक्तिगत पेशी पर भी सवाल खड़े किए।

कानून मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी अब तक न्यायालय में व्यक्तिगत पेशी से बचने के लिए वकील खड़े करते रहे हैं और अब सूरत की कोर्ट में खुद पहुंचे हैं, जबकि यहां व्यक्तिगत पेशी की आवश्यकता नहीं थी। आरोप लगाया कि कांग्रेस न्यायालय को दबाव में लेने के लिए ड्रामा कर रही है।

वहीं, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पिछड़ों के अपमान के मुद्दे पर फिर राहुल को घेरने का प्रयास किया।

उन्होंने कहा कि पिछड़ों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एक बार नहीं, बल्कि बार-बार कांग्रेस और राहुल गांधी ने पिछड़ों का अपमान किया है। माफी तक नहीं मांगी।

अनुराग ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पिछड़ों को दबाया और डराया है। संसद सत्र को खराब किया है। विदेशी ताकतों से सहायता मांगी है। आखिरकार ये दबाव बनाकर किसको डराना चाहते हैं? क्यों राज्यों के मुख्यमंत्री को सब काम छुड़वाकर यहां लाया गया।

अमेरिका में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दो की मौत

वाशिंगटन, 3 अप्रैल (वार्ता)। अमेरिका के राज्य अलबामा में शेल्बी काउंटी में एक मेडिकल हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चालक दल के दो सदस्यों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया है। स्थानीय शेरिफ कार्यालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। शेल्बी काउंटी शेरिफ के कार्यालय प्रमुख क्ले हैमैक ने एक प्रेस वार्ता में कहा, यह घटना रविवार को स्थानीय समयानुसार शाम करीब 5.30 बजे इस वक्त हुई, जब एक पदयात्री के सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने पर, हेलीकॉप्टर को उसकी मदद को लिए भेजा गया था। उसी दौरान, कुछ तकनीकी खामी के कारण हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया।

सपा की "दलित मैत्री" नीति से मायावती...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- एक पुराने बसपा नेता का कहना है कि, भाजपा सरकार ने जिस सफलता से सैन्ट्रल एजेन्सियों का विरोधियों के खिलाफ प्रयोग करने की नीति अपनाई, और जो लालू यादव के खिलाफ सफलता से उपयोग की गईं, उससे मायावती विचलित हो गई, और उनकी रही सही हिम्मत तब टूट गयी जब उनके मु.मंत्री काल में उनके पावरफुल प्रिंसिपल सैक्रैटरी रहे नेतराम पर 2019 में सैन्ट्रल एजेन्सियों ने धावा बोल दिया।
- इस घबराहट के बाद, मायावती का राजनीतिक वर्चस्व समाप्त होता चला गया तथा अब यह हालत है कि, सपा उनके वोट बैंक पर खुल्लम-खुल्ला कब्जा करने का प्रयास कर रही है।

था। उन्होंने कहा कि अगर सपा ने गठबंधन सरकार कांशीराम के मिशनरी विचारों के अनुसार चलाई होती तो गठबंधन में कोई दरार न आई होती तथा हमारा गठबंधन देश पर शासन कर रहा होता। लेकिन सपा की दलित-विरोधी तथा पिछड़ा वर्ग-विरोधी राजनीति एवं मुस्लिमों को धोखा देने की प्रवृत्ति के कारण यह संभव नहीं हो सका। मायावती ने आगे कहा कि भाजपा इस समय उसी का फायदा उठा रही है।

जहाँ यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि पिछड़ी जातियाँ, खासतौर से दबदबा रखने वाला यादव समुदाय दलितों का शोषण एवं उत्पीड़न करता रहा है, लेकिन आज, वर्तमान वातावरण में इस मुद्दे का राग अलापना दरअसल ग़ैर-भाजपा विपक्षी मोर्चे को कमजोर करने का एक सुनियोजित प्रयास है।

देश के इस सबसे बड़े राज्य में बसपा वर्ष 2012 से ही तब से राजनीति आधार खोती रही है, जब मायावती की यह पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई थी। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ 17 सीटें ही जीत सकीं और वर्ष 2022 के चुनावी संघर्ष में पार्टी सिर्फ एक सीट पर ही सिमटकर रह गई।

यद्यपि, मायावती एक कठोर परिश्रमी राजनेता रही हैं, लेकिन वह स्व. कांशीराम के मजबूत एवं ठोस कार्यों को आधार कर सत्ता तक पहुंची। कांशीराम ने दलितों के बीच व्यवस्थित ढंग से कार्य किया था।

मायावती ने कभी भी कोई लम्बा राजनीतिक संघर्ष नहीं किया और वह शायद ही कभी जेल गई या उन्होंने शायद ही कभी राजनीतिक अत्याचारों का सामना किया।

इसके परिणामस्वरूप, वह पिछले कुछ वर्षों से हाशिए पर रहती आई हैं, क्योंकि वह मोदी सरकार द्वारा ई.डी., आई.टी. और सी.बी.आई. के जरिए की जा रही कार्रवाहियों से वाकिफ हैं। बसपा के एक सीनियर नेता ने गुप्त रूप से बताया कि केन्द्रीय जांच एजेन्सियों द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के साथ किए गए व्यवहार ने मायावती को भयभीत कर दिया है।

वर्ष 2007 से 2012 तक जब मायावती मुख्यमंत्री थीं, तब नेतराम उनके प्रधान सचिव थे, लेकिन मोदी सरकार की केन्द्रीय जांच एजेंसियों ने वर्ष 2019 में जब से नेतराम पर छापे मारे, मायावती के कार्य पर तभी से कुठाराघात होता रहा है, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी या उनकी नीतियों पर प्रहार करना बंद कर दिया है, जबकि वह कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी के प्रति कठोर रहती आयी हैं।

राहुल को कुछ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मोदी ने बहुत गहराई से और सोच विचारकर काम किया है। उसके अनुसार यह सोचा गया है कि राहुल फिलहाल जेल से बाहर रहें तथा अपने केस लड़े, जिससे कि वे कांग्रेस पार्टी के संचालन में भी सक्रिय रहे और पार्टी का नेतृत्व करते रहें। वरना दूसरी स्थिति में प्रियंका गांधी ही है, जो राहुल गांधी के खाली स्थान को भरने के लिये आगे आ सकती हैं।

बहुत से कांग्रेसजनों ने राहुल गांधी के स्थानापन्न अगले नेता के रूप में, प्रियंका गांधी की ओर रूख करना शुरू भी कर दिया है।

जब तक राहुल गांधी की दोष-सिद्धि का निर्णय उलट नहीं जाता, तब तक वे "डिस्क्वालिफाइड" ही रहेंगे। तब तक गुजरात की किसी अदालत से उन्हें राहत मिल पाना थोड़ा मुश्किल ही है।

समझा जाता है कि राहुल गांधी निर्धारित तिथि से पहले ही 12, तुगलक लेन वाला अपना सरकारी बँगला खाली कर देंगे।

अचानक सऊदी अरब ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- भारत पर रूस के क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत ने रूस से ऑयल खरीद के काफी लंबे सौदे कर रखे हैं।

कटौती की जाए। लेकिन सऊदी अरब पहले विपरीत अब अमेरिका को आँखे दिखा रहा है। वह हाल ही चीन से बढ़ी अपनी निकटता से शायद उत्साहित है।

चीन ने एक लम्बे समय से संघर्षरत दोनों पड़ोसी देशों, सऊदी अरब और ईरान के बीच एक शांति समझौत करा दिया है। ये दोनों देश कई दशकों तक आपस में बुरी तरह से लड़े। ईरान समर्थित हाउती उग्रवादियों ने सऊदी अरब के ऑयल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स पर गंभीर हमला किया था। सऊदी अरब, ईरान द्वारा परमाणु हथियार विकसित किए जाने और उन्हें क्षेत्र में तैनात किए जाने को लेकर भी आशंकित है। उसे डर है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का निशाना सऊदी अरब और उसके मित्र देश हैं।

लेकिन दोनों देशों के बीच चीन द्वारा कराए गए समझौते से एक तरह की शांति बहाल हुई है और तनाव थोड़ा कम हुआ है, किन्तु विशेषज्ञ महसूस करते हैं कि इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच बैर-भाव इतना गहरा है कि शांति लम्बे समय तक शायद ही कायम रहे।

लेकिन, फिलहाल सऊदी अरब और ईरान के बीच हुए समझौते और ओ.पी.ई.सी. (ओपैक) व उसके मित्र देशों के संगठन को चीन व रूस से मिले समर्थन ने सऊदी अरब में इतनी हिम्मत जुटा दी है कि वह अमेरिका की उपेक्षा कर रहा है। अब अमेरिका के पास सऊदी अरब का मुकाबला करने के बहुत कम विकल्प हैं। इस कदम से रूस को त्वरित लाभ होगा क्योंकि उसे तेल से जो आय प्राप्त नहीं हो रही थी, उसमें वृद्धि होगी। रूस ने तुरन्त प्रभाव से घोषणा की कि वह अपने तेल उत्पादन में इतनी ही कटौती करेगा, जितनी कि सऊदी अरब ने की है। सऊदी की ऑयल इण्डस्ट्री ने तेल के उत्पादन में 5 लाख डॉलर प्रतिदिन की कमी की घोषणा की है और अब रूस भी ऐसा ही करने का वादा कर रहा है। इस प्रकार रूस सुखद स्थिति में रहेगा। उसकी आय बढ़ेगी जबकि वह कम उत्पादन करेगा और बिक्री भी और प्रति यूनिट ऑइल बिक्री से होने वाली आय बढ़ जाएगी। इससे रूस को पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से निपटने में मदद मिलेगी।

रूस से तेल खरीद जारी रखने और अनुबंध को बढ़ाने के भारत के फैसले से भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत का रूस से तेल खरीद का दीर्घगामी अनुबंध है। हालांकि जब तक भारत और रूस के तेल खरीद अनुबंध का ब्यौरा स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक यह पता नहीं चलेगा कि भारत भविष्य में कब तक रूस से तेल खरीदता रहेगा।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908